दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(PC)524/VII - CPC/Allowances

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 23-08-2017

आर बी ई सं/RBE No. 88 / 2017

पी बी सी सं/ PBC No.139 / 2017

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,

(As per mailing list –'A')

विषय/Sub:Special (Duty) Allowance for Railway Employees serving in the North Eastern Region & Ladakh –Recommendations of Seventh Central Pay Commission.

*****

A copy of Railway Board letter No. F(E)/I/2017/AL-4/2 dt.10-08-2017 (RBE No.88/ 2017) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.Srinivasan)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

PC-VII No. 35

RBE No. 88/2017

No. F(E)I/2017/AL-4/2 **New Delhi, dated 10.08.2017**

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub: Special (Duty) Allowance for Railway Employees serving in the North Eastern Region & Ladakh – Recommendations of Seventh Central Pay Commission.

Consequent upon the acceptance of the recommendations of Seventh Central Pay Commission by the Government, the President, in supersession of all existing order issued on the subject from time to time, is pleased to decide that Railway employees, serving in the North Eastern Region and Ladakh, shall be paid Special Duty Allowance (SDA) at the rate of 10% of Basic Pay.

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Levels in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like Special Pay etc.

3. Special Duty Allowance will not be admissible along with Tough Location Allowance. Employees will have the additional option to avail of the benefit of Special Compensatory (Remote Locality) Allowance as per 6th Central Pay Commission rates along with Special Duty Allowance at revised rates.

4. Special Duty Allowance shall not be admissible during the periods of leave/training/tour etc. beyond full calendar month(s), in case, the employee is outside the North-Eastern Region and Ladakh during leave/training/tour etc. The allowance shall not be admissible during suspension and joining time.

5. **These orders shall take effect from 1st July, 2017.**

6. Hindi version is enclosed.

7. Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Deputy Director Finance (Estt.),
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पीसी-VII सं. 35
आरबीई सं. 88/2017

सं.एफ(ई)1/2017/एल-4/2 नई दिल्ली, दिनांक 10.08.2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें आदि।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं लद्दाख में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष (ड्यूटी) भत्ता ।

सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने, समय-समय पर इस विषय पर जारी सभी मौजूदा आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, यह सहर्ष निर्णय लिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को मूल वेतन के 10% की दर पर विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में शब्द 'मूल वेतन' का अभिप्राय पे मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त वेतन से है, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

3. कठिन स्थान भत्तों के साथ-साथ विशेष ड्यूटी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। कर्मचारियों के पास संशोधित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ-साथ छठे केंद्रीय वेतन आयोग की दरों के अनुसार विशेष प्रतिपूरक(दूरस्थ स्थान) भत्ते का लाभ प्राप्त करने का अतिरिक्त विकल्प होगा।

4. यदि कर्मचारी छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरा/आदि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख से बाहर है तो पूर्ण कैलेंडर महीने (महीनों) में छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरा आदि की अवधि के दौरान विशेष ड्यूटी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। निलंबन के दौरान और ज्वाइनिंग के समय यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

5. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

6. कृपया पावती दें।

सोनाली चतुर्वेदी

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक वित्त(स्था.)
रेलवे बोर्ड